

आर्थिक विकास के साथ ही साथ नष्ट होती हमारी संस्कृति एवं परम्परा

M, egEn 'kehe

एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य
राजकीय महाविद्यालय, महाराजगंज

Abstract

कोई भी देश अपनी प्रगति एवं उपलब्धियों पर तब तक गर्व नहीं कर सकता जब तक कि उसके यहाँ शिक्षा का स्तर उच्च न हो। सम्पूर्ण भारतवर्ष के विकास के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को सस्ती और तकनीकी, ज्ञानवर्द्धक शिक्षा सुलभ कराई जानी चाहिये। वर्तमान में जो शिक्षा प्रदान की जा रही है वह छात्रों को भ्रमित करने का ही काम अधिक कर रही है। शिक्षा इस प्रकार से होनी चाहिए जिससे कि छात्र अपने जीवन काल में कुछ कमा खा सके। राश्ट्र की बेरोजगारी कम हो सके तथा सभी को आजीविका चलाने का अधिक से अधिक अवसर मिल सके। शिक्षा उत्पादोन्मुख होनी चाहिए, क्योंकि उत्पादन में वृद्धि ही आर्थिक विप्लव का मूल आधार है। गान्धीजी ने शिक्षा के क्षेत्र में इस कमी को पहचान लिया था। उन्होंने शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ने का प्रयास किया था। आज का समय आधुनिक है। हम आधुनिक समाज में जी रहे हैं, अतः शिक्षा को भी तकनीकी होना चाहिए, जिससे कि उद्योगों का विकास हो सके और भारत उद्योगों के विकास से और आगे बढ़ सके।

Introduction

किसी देश का आर्थिक रूप से मजबूत होना, उस देश के निवासियों के लिए गर्व की बात होती है। हमारा देश भी लगातार सभी क्षेत्रों में अपनी सफलता के झण्डे गाँड़ता चला जा रहा है। यहाँ की मेधा का ढंका आज सारे विश्व में बज रहा है, इतना सब होने के बाद भी हमारे जीवन मूल्यों में कमी दृष्टिगोचर होती है। भारत की आत्मा तो उसके गाँवों में बसती है, अगर भारत को जानना एवं समझना है तो पहले हमें उसके गाँवों के बारे में जानना होगा। कालांतर में गाँव की समाजिक संरचना एवं संगठन में अमूल-चूल परिवर्तन हुआ है। भारत सरकार द्वारा चालू की गई कुछ योजनाओं यथा- डिजिटल इंडिया। स्टार्टअप इंडिया एवं सर्व शिक्षा अभियान. नरेगा तथा सूचना कान्ति ने इसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। भारतीय ग्रामवासियों की जीवन शैली में अभूतपूर्व ढंग से बदलाव आया है। भारतीय गाँव आज आर्थिक रूप से सम्पन्न बन गए हैं। गाँव की प्रति व्यक्ति कृय षक्ति बढ़ गई है।

आज राज्य तथा केन्द्र दोनों ही सरकारें गाँव की उन्नति के लिए काफी धन खर्च कर रहीं हैं। आज के गाँव निश्चित रूप से पहले के जैसे नहीं रह गये हैं। आज हर एक गाँव में सड़कें, नहरें, पाठशालाएँ, टेलीविजन, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर आदि सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। गाँवों में विकास की यह प्रक्रिया निरन्तर चल रही है। खेत जोतने के लिए अब किसान को बैलों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं रह गई है। जोताई से लेकर बोआई, मड़ाई आदि सभी चीजों की आधुनिक मशीनें बाजार में उपलब्ध हैं। आज गाँव संक्रमण के ऐसे दौर से गुजर रहा है, जहाँ प्रत्येक ग्रामवासी आडम्बर युक्त जीवन जी रहा है। आज वह सिर्फ अपने बारे में सोचता है। उसे अन्य किसी ओर से कोई सरोकार नहीं है। किसी दूसरे की तरक्की को देखकर वे अपने मन में उसके प्रति ईर्ष्या करते हैं। आज ग्रामीण समाज पहले जैसा स्थिर, कटु, पिछड़ा, रुढ़िवादी, असभ्य एवं संतोशी नहीं रहा है। ग्रामीण समाज में बदलाव की यह प्रक्रिया उसके विभिन्न आयामों पर चल रही है।

चाहें वह सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक या फिर आर्थिक हो। ग्रामिणों ने प्रत्येक क्षेत्र में अपनी गतिशीलता दर्ज करवायी है। गाँव अब सामाजिक ईकाई ही नहीं राजनीतिक ईकाई के रूप में उभर रहा है।

आधुनिकीकरण तथा आर्थिक सुधारों के चलते जहाँ सकारात्मक परिवर्तन आये हैं वहीं साथ ही साथ नकारात्मक परिणाम भी सामने आये हैं, यथा— जातीय संघर्ष, गुटबाजी, छलकपट, नशाखोरी, आडम्बर, उपभोग की संस्कृति का विकसित होना, अश्लीलता को बढ़ावा मिलना आदि। जिसके परिणामस्वरूप गांव का सरल एवं सादा जीवन जटिल एवं आडम्बरयुक्त बन रहा है। वहां उपभोक्तावाद लगातार अपने पैर पसार रहा है। जैसे-जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पूजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ती जा रही हैं, वैसे-वैसे उसका भूमंडलीकरण होता जा रहा है और उस ग्रामीण समाज का षहरीकरण होता जा रहा है। पुराने मानक एवं मूल्य लगातार बदलते जा रहे हैं। वहां इसके स्थान पर नये प्रकार के तनाव एवं राग-द्वेष एवं द्वन्द्व पनप रहे हैं। रिश्तेदारी एवं नातेदारी संबंधी मूल्यों और प्रेम-व्यवहार में अंतर आ रहे हैं। अब वह धनार्जन के नये-नये तौर-तरीकों से परिचित हो रहे हैं। अब उनके पास पूंजी का कोई विशेष अभाव नहीं रह गया है, जिसका प्रभाव गांवों में होने वाली मंहगी षादीयों या विवाहों या फिर भव्य कार्यक्रमों और राजनीतिक क्रियाकलापों में प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। इतना सब होने के बाद भी फिर भी ऐसा लगता है कि हमारे गांव पिछड़ते चले जा रहे हैं। जिसकी वजह से किसान खेती छोड़ते चले जा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों से उनका लगातार पलायन हो रहा है।

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कृषि और इससे जुड़े हुये विभिन्न क्षेत्रों का सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम संक्षेप में जी0 डी0 पी0 कहते हैं, का योगदान 2009-2010 में महज 0.2 प्रतिशत ही था, जो यह दर्शाता है कि हमारी कृषि का भविष्य अन्धकारमय है। गांवों के नौजवान न तो कृषि में ही रुचि ले रहे हैं और न उन्हें गांव में रहना ही रुचिकर लगता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के एक अध्ययन के मुताबिक लगभग 40 प्रतिशत किसान खेती छोड़ना पंसद करेंगे यदि उन्हें ऐसा करने की छूट दे दी जाय। दुर्भाग्यवश, उनके लिए षहरी मलिन बस्तियों में जाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं हैं। किसानों की सर्वाधिक बदतर स्थित आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र जैसे उन अग्रणी राज्यों में है जो 1991 में प्रारम्भ नयी आर्थिक नीतियों से खासे लाभान्वित हुए हैं, और प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से काफी आगे हैं।

इन विकट स्थितियों के चलते इन राज्यों के हजारों किसानों ने आत्महत्या तक कर लिया। जिन किसानों ने आत्महत्या नहीं की है उनकी स्थिति आत्महत्या करने वाले किसानों से बहुत अच्छी नहीं हैं। आत्महत्या से सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र है। इसी प्रकार से देश के षोश गांवों के किसानों की स्थिति भी विदर्भ एवं उसके जैसे प्रभावित अन्य राज्यों के किसानों से अलग नहीं हैं। आज विकास की इस दौड़ में गांवों की प्राचीन विरासत एवं परम्परा कहीं विलुप्त न हो जाये इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारे गांव ही भारतीय संस्कृति एवं परम्पराओं के प्रतिबिम्ब हैं। इन गांवों से ही हमारी पुरातन परम्पराएं, रीति-रिवाज, प्रथाये, रूढ़ियां एवं संस्कृति आदि आज भी जीवित हैं। गांव की युवा पीढ़ी आधुनिक संचार साधनों का तो उपयोग करे मगर कहीं इसके चुंगल में न फंसकर रह जाये इस बात पर ध्यान रखने की जरूरत है। संचार साधनों में हुई प्रगति का लाभ आज प्रत्येक ग्रामिण उठा रहा है। पहले जहाँ लोगों के पास टेलिफोन जैसी बुनियादी चीज नहीं थी, वहीं आज प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में आधुनिक मोबाइल सेट है। गांवों के प्रत्येक चट्टी-चौराहों पर साइबर कैफे खुले हैं और जहाँ नहीं खुले हैं वहां पर भी तेजी के साथ खुलते ही चले जा रहे हैं।

इन साइबर ढाबों/साइबर कैफों पर गांवों के नौजवानों की भीड़ कभी भी देखी जा सकती है। गांवों में होने वाले इन परिवर्तनों के नकारात्मक प्रभाव भी अब सामने आ रहे हैं। इन प्रभावों ने गांवों की प्राचीन परम्परा और उसकी जड़ों को हिलाकर रख दिया है। गांव की प्राचीन परम्परा एक मुट्ठी में बन्द रेत की तरह से फिसल कर बाहर निकलती चली जा रही है। इस स्थिति ने उसे किंकर्तव्यविमूढ़ बना दिया है। वह समझ नहीं पा रहा कि आने वाली नई तकनीकी का अपने गांव में स्वागत करे अथवा उसका विरोध करे। प्राचीन मान्यताओं तथा आधुनिकता के बीच में पड़ कर वह छटपटा रहा है, उसका दम फूल रहा है।

एक दिशाहीनता का वह अनुभव कर रहा है। शीघ्रता से होते जा रहे षहरीकरण को वह बस मूक दर्शक बन करके देख रहा है। कृषि तथा पशुपालन जैसे व्यवसाय जो कि उसकी जीविका का एक आधार बिन्दु था अब उससे दूर होता चला जा रहा है। कृषि योग्य भूमि का व्यावसायिकरण होता चला जा रहा है। देश में इस समय लगभग छह लाख गांव हैं जिनमें से चार लाख गांवों में खाद्यान्न का उत्पादन होता है। जरूरत है उनको प्रेरित करने की ताकि वे शिक्षा के साथ ही साथ आधुनिक कृषि ज्ञान को भी समझे तथा उसे सीखे। “उत्तम खेती मध्यम बान” यह पुरानी कहावत एकदम से सटीक है। सच तो यह है कि ग्रामीण विकास के बिना हमारे देश की उन्नति सम्भव ही नहीं है।

भारत के आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका बड़ी ही महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी एक सत्य है कि इसके मूल्यों में कमी आयी है। फलस्वरूप शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में प्रतिवर्ष इजाफा देखने को मिल रहा है। ज्यों-ज्यों शिक्षा का व्यावसायिकरण होता गया वैसे ही इसके नैतिक मूल्यों में कमी देखने को मिल रही हैं। आज के विश्वविद्यालय केवल कागज की डिग्री बॉटने वाले केन्द्र बन कर रह गये हैं। विश्व के टाप के दो सौ कालेजों की लिस्ट में हमारे देश के एक भी कालेज का नाम न मिलना हमें अब कोई अचम्भीत नहीं करता। अपने देश से काफी छोटे-छोटे कई अन्य देशों के कालेजों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। अभी हाल में दुनिया के जाने-माने विश्वविद्यालयों के एक संगठन के आकलन से एक रिपोर्ट आई है। यूनिवर्सिटास-21 की इस रिपोर्ट ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारी पोल ही खोल दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार, उच्च शिक्षा में भारत का स्थान 48 वां है। इस सूची में हमारे देश का स्थान ब्रिक देशों, ब्राजील, रूस एवं चीन के बाद सबसे अंत में आता है। इस सूची में पहला स्थान अमेरिका को दिया गया है, वहीं दूसरे स्थान पर स्वीडन और तीसरे पर कनाडा का नाम है। हमारे देश के विश्वविद्यालयों की इस दयनीय दशा के लिए केन्द्र और राज्य सरकारें दोनों ही बराबर की जिम्मेदार हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रिपोर्ट बतलाती है कि देश में अभी भी 13 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों की कमी है। कोई भी देश अपनी प्रगति एवं उपलब्धियों पर तब तक गर्व नहीं कर सकता जब तक कि उसके यहाँ शिक्षा का स्तर उच्च न हो। सम्पूर्ण भारतवर्ष के विकास के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को सस्ती और तकनीकी, ज्ञानवर्द्धक शिक्षा सुलभ कराई जानी चाहिये। वर्तमान में जो शिक्षा प्रदान की जा रही है वह छात्रों को भ्रमित करने का ही काम अधिक कर रही है। शिक्षा इस प्रकार से होनी चाहिए जिससे कि छात्र अपने जीवन काल में कुछ कमा खा सके। राश्ट्र की बेरोजगारी कम हो सके तथा सभी को आजिविका चलाने का अधिक से अधिक अवसर मिल सके। शिक्षा उत्पादोन्मुख होनी चाहिए, क्योंकि उत्पादन में वृद्धि ही आर्थिक विप्लव का मूल आधार है। गाँधीजी ने शिक्षा के क्षेत्र में इस कमी को पहचान लिया था।

उन्होंने शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ने का प्रयास किया था। आज का समय आधुनिक है। हम आधुनिक समाज में जी रहे हैं, अतः शिक्षा को भी तकनीकी होना चाहिए, जिससे कि उद्योगों का विकास हो सके और भारत उद्योगों के विकास से और आगे बढ़ सके। आर्थिक विकास के क्षेत्र में हुए विभिन्न शोध इस बात की पुष्टि करते हैं कि शिक्षा, विज्ञान एवं तकनीकी आर्थिक विकास में अपना लगभग 50 फीसदी से ज्यादा ही योगदान देते हैं। अतः हमें शिक्षा के साथ ही साथ विज्ञान के भी महत्व को समझना होगा। हमारे देश के वैज्ञानिकों का डंका आज पूरे विश्वभर में बज रहा है, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि हमारे ही युवा वैज्ञानिक आज अच्छे वेतन के लालच में अन्य विकसीत देशों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं।

दूसरे विश्वयुद्ध के बाद मानवीय परिदृश्य में अनेक नाटकीय मोड़ आयो बीते हुए कल का साम्राज्यवादी डॉंचा चरमराफर विखारने लगा और एक के बाद एक पुराने उपनिवेशों के स्थान पर नये स्वाधीन राज्यों का उदय हुआ। इन नव-स्वाधीन राज्यों में नयी सांस्कृतिक चेतना जागीय वे अपनी राष्ट्रीय अस्मिता के प्रति सजग और सचेत हुए। उन्होंने सांस्कृतिक पहचान के कुछ प्रतिष्ठा-चिन् अपनाये-राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रीय देश-भूषा राष्ट्रीय एकीकरण के लिए ये जसरी थे। पर काफी नहीं। अभाव की संस्कृति दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में विघटनकारी सिद्ध हो सकती है। दमित और अवरुद्ध सांस्कृतिक आकांक्षाएँ क्षेत्रीय लघु और सूक्ष्म सांस्कृतिक आन्दोलनों का रूप ले सकती हैं जिनका सम्मिलित प्रभाव देश के समूचे ढाँचे को डगमगा सकता है। वैसे भी स्वाधीनता को अर्थ देने के लिए यह आवश्यक भी था कि भूखों को भोजन मिले, जनता निरक्षरता के अन्धकार से बाहर निकले, बेपरो के लिए आवास की व्यवस्था हो, रोगियों की चिकित्सा का प्रबन्ध हो। यह किसी भी स्वाधीन देश के लिए न्यूनतम कार्यसूची थी, पर इसके लिए भी संसाधनों का सुनियोजन और निवेश आवश्यक था। नवस्वाधीन देशों ने नियोजित आर्थिक विकास का रास्ता अपनाया। सम्पन्न देशों ने उनका उत्साह बढ़ाया और उन्हें आर्थिक और तकनीकी सहायता देने का आश्वासन भी दिया। बाद में यह सहायता आयी भी, पर वह न पर्याप्त थी और न समय पर ही आयी। उसके साथ कुछ शर्तें भी थीं जिनके परिणाम बाद में स्पष्ट हुए।

आर्थिक विकास के कार्यक्रम के प्रारम्भिक काल में उसकी परम्पराओं और संस्कृति से सीधी टकराहट नहीं हुई। इस बीच विकास विशेषज्ञों की अच्छी-खासी फौज मैदान में उतर आयी और मोंगे-बिन मांगे अपनी सलाह विकासशील देशों को देने लगी। विदेशी ऋण और सहायता पाने के लिए उनकी सलाह मांगना और उस पर चलना जरूरी था। इन तथाकथित विशेषज्ञों ने भी पहले यही सुझाव दिया कि विकास कार्यकर्ता

सांस्कृतिक मान्यताओं के प्रति संवेदनशील रहें और स्थापित परम्पराओं से न टकराएं। योजनाओं से जब आपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए तब असफलता के कारणों का विश्लेषण किया गया। दोषी पाया गया परम्पराओं को। नयी मांग थी सांस्थानिक ढाँचे, अभिवृत्तियों और मूल्यों को बदलने की। अल्पज्ञ विशेषज्ञ, जो विकास के क्षेत्र में सर्वज्ञ बने घूम रहे थे, ऐसा कोई मन्त्र नहीं दे सके जिससे यह तत्काल सम्भव हो सके। परम्परा की सृजनात्मक ऊर्जा से भी वे अपरिचित थे। उन्हें ये भी अहसास नहीं था कि परम्परा की अवरोधात्मक प्रतिक्रिया विकास के समूचे एजेण्डा को अस्त-व्यस्त कर सकती है। नियोजन, प्रबन्धन, संचार नीति के दोष आदि भी विकास असफलता के उत्तरदायी हो सकते हैं, परन्तु इनकी ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। संस्कृति और परम्पराएं कठघरे में रहीं, चारों ओर से उन पर हमले हुए और होते रहे। सब सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक मूल्यों तथा अभिवृत्तियों को बदल देना चाहते थे, पर ऐसा कर सकने की कोई कारगर सामाजिक प्रविधि उपलब्ध नहीं थी।

आधुनिकीकरण का आकर्षण, आर्थिक विकास के अतिरिक्त जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी अभिव्यक्ति पा रहा था एक छोटा-सा वर्ग, जो सम्पन्न था और विकासक्रम के लाभों से जिसकी स्थिति और भी मुह हो गयी थी, आधुनिकता का प्रतिरूप बना। उसकी जीवन शैली बदली, विचार शैली नहीं। यह छन आधुनिकता थी जो अहम् के साथ अनेक वहम भी पाल रही थी। यह अभिजात्य और सम्पन्नता की झीनी परत पधिमिकरण कोही आधुनिकीकरण मान बैठी थी। उसने विवेक के तर्क, परानुभूति, भूमिकाओं की सचलता और सक्रियता आदि गुण, जो आधुनिकता के आधार लक्षण हैं, नहीं अपनाये, भोगवादी और प्रदर्शनवादी जीवन-शैली जसर अपना ली। बौद्धिक क्षेत्र में आये परिवर्तन और भी आश्चर्यजनक तथा साथ ही चिन्ताजनक भी यो अकादमिक क्षेत्र में देशज चिन्तन पीछे फूटता गया और पधिमि विचार प्रणालियों विचार-जगत पर छा गयीं। यह बी बौदिक उपनिवेशवाद की स्वीकृति, जिसके लिए कुछ प्रलोभन तो थे पर विशेष दवाव या आग्रह नहीं। साहित्य और कला पर भी पश्चिमी प्रभाव स्पष्ट को अपनी जड़ों से कटा यह बौद्धिक वर्ग अनुकरण का उत्सवीकरण कर रहा था। आत्म-रति में लीन यह वर्ग अपने व्यापक सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति उदासीन था। कभी-कभी उसकी चेतना जागती थी किन्तु उसकी प्रतीकात्मक सक्रियता झूठा आत्म-सन्तोष भले ही दे, समाज को दिशा दे सकने में समर्थ नहीं थी

संदर्भ सूची

1. इंटरनेशनल सेमिनार, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ- डॉ० नवीन शंकर पाण्डेय
2. जनरल ज्ञान दायिनी समाज विज्ञान शोध पत्रिका, (पृष्ठ 147) दिसम्बर 2012
3. भारतीय अर्थव्यवस्था, डॉ० जे० सी० पन्त एवं डॉ० एस० सी० जैन
4. प्रतियोगिता किरण (हिन्दी मासिक) अगस्त, 2003
5. आई० ए० एस० किरण (हिन्दी मासिक) अगस्त, 2003